फा.सं.: 19012/01/2023-पीसी

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(पीसी प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 02.07.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अप्रैल, 2023 के लिए प्रमुख गतिविधियों का मासिक सारांश।

*****

अधोहस्ताक्षरी को अप्रैल, 2023 माह के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियों के सारांश की एक प्रति सूचना हेतु प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(मनोज कुमार सिंह)

उप सचिव

दूरभाष: 011- 23340270

ईमेल: singh.mk@nic.in

सेवा मे

मंत्रिपरिषद के सदस्य

प्रति संलग्नकों सहित अग्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी सचिव (सभी मंत्रालय/विभाग)
2. कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ:

1. सचिव (जनजातीय कार्य) के पीपीएस
2. एनआईसी सेल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

विषय: अप्रैल, 2023 माह के लिए प्रमुख गतिविधियों का मासिक सारांश।

*****

यह अप्रैल, 2023 माह के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में है.

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)</u>

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) पात्र अनुसूचित जनजातियों को उनकी आजीविका के लिए स्व-सशक्तिकरण उद्यम शुरू करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस संबंध में, वर्ष 2023-24 के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की स्थिति इस प्रकार है:

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	मद	वित्तीय वर्ष 2023-24		पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान निष्पादन
		वार्षिक लक्ष्य*	30.04.2023 तक उपलब्धि	
1	स्वीकृत	**250.00**	**5.93**	**2.19**
2	संवितरण	**250.00**	**25.01**	**21.85**

* वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुमानित निधि उपलब्धता के आधार पर मंजूरी और संवितरण का वार्षिक लक्ष्य तैयार किया गया है। यह कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्तावों और संवितरण के लिए उपलब्ध निधि के अनुसार भिन्न हो सकता है।

2.1 वर्ष 2023-24 के दौरान अनुमानित निधि उपलब्धता के आधार पर, एनएसटीएफडीसी ने उक्त वर्ष के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सैद्धान्तिक (अनुमानित) आवंटन के रूप में ₹250 करोड़ निर्धारित किए हैं। तदनुसार, ऋण प्रस्तावों को अग्रेषित करने के अनुरोध के साथ आवंटन पत्र संबंधित चैनलाइजिंग एजेंसी (यों) को भेज दिए गए हैं।

2.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय के निदेशक (आजीविका) ने एनएसटीएफडीसी-मुख्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया और निगम की योजनाओं के कार्यान्वयन के तंत्र को समझने और लक्ष्य समूह तक पहुंचने के लिए नए मार्ग तलाशने के लिए परियोजना विभाग अधिकारियों के साथ बातचीत की।

2.3 लक्ष्य समूह के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए, एनएसटीएफडीसी ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (आरएमजीबी) के साथ एक समझौता किया है। राजस्थान राज्य में एनएसटीएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आरएमजीबी एक अन्य एजेंसी होगी।

2.4 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के अधिकारियों ने एनएसटीएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के तहत अजजा के पात्र सदस्यों को रियायती ऋण देने के लिए एनएसटीएफडीसी की कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक के रूप में आईपीपीबी को शामिल करने की संभावना तलाशने के लिए एनएसटीएफडीसी कार्यालय का दौरा किया।

2.5 निगम ने माह के दौरान सेल प्रदर्शनी मैदान, राउरकेला (ओडिशा) में आयोजित क्षेत्रीय आदि महोत्सव में भाग लिया। इस आयोजन के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने ओडिशा राज्य में अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए एक स्टॉल लगाया था।

इस कार्यक्रम के दौरान, एनएसटीएफडीसी के अधिकारी ने आजीविका बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर, राउरकेला का दौरा किया और प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की।

<u>वन अधिकार अधिनियम</u>

3. राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत 30.11.2022 तक 44,66,617 दावे (42,97,245 व्यक्तिगत और 1,69,372 सामुदायिक) दायर किए गए हैं और 22 ,49,671 शीर्षक (21,46,782 व्यक्तिगत और 1,02,889 सामुदायिक) वितरित किए गए हैं। कुल 39,79,543 (89.10%) दावों का निपटारा किया जा चुका है।

<u>"पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढावा देने के लिए विपणन और संभार (रसद) विकास (पीटीपी-एनईआर)" का शुभारंभ</u>

4. भारत सरकार के जनजातीय कार्य केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने दिनांक 18.04.2023 को इंफाल, मणिपुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लाभ के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना "पूर्वोत्तर क्षेत्र (पीटीपी-एनईआर) के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और संभार (रसद) विकास" का शुभारंभ किया।

5. केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए एहतियाती उपाय करने के लिए आवश्यक उपायों और केंद्र की सहायता से शुरू किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करने हेतु पोर्ट ब्लेयर संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27.04.2023 को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

पीवीटीजी समुदाय के लिए समावेशी विकास और समग्र कल्याण के लक्ष्य की दिशा में अनुभवों, सुझावों और विचारों के आदान-प्रदान की अनुमति प्रदान करने से यह चर्चा सभी के लिए उपयोगी साबित हुई।

6. क्षेत्रीय आदि महोत्सव का आयोजन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट के सहयोग से राउरकेला, ओडिशा में 07.04.2023 से 15.04.2023 तक किया गया।

इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों से 275 कारीगरों ने अपने शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का प्रदर्शन करने के लिए भाग लिया, जिसमें वीडीवीके, पीवीटीजी, एफपीओ, जीआई टैग स्टॉल, बाजरा स्टॉल आदि द्वारा लगाए गए स्टॉल शामिल थे।

शिल्प स्टालों और कारीगरों के अलावा, इस कार्यक्रम में संथाल, धारुआ, परोजा, ओरम, किसान, पौडीभुयान (पीवीटीजी), डोंगरिया कांध (पीवीटीजी) और कुटियाकांध (पीवीटीजी) जैसे विभिन्न जनजातियों से संबंधित लगभग 140 जनजातीय कलाकारों द्वारा दैनिक आधार पर 09 दिनों की अवधि में सांस्कृतिक प्रदर्शन में भी भागीदारी लेते हुए देखा गया है।

7. ई-गवर्नेंस को डिजिटल इंडिया का अनिवार्य हिस्सा बनाने के क्रम में, इस मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2023 माह के दौरान ई-ऑफिस में 81 ई-फाइलें बनाई गई हैं।